All Inclusive IAS - Prelims 2024

← English video

Economy Class-06

हिंदी वीडियो →

Fertilizers

- ❖ Dept of Fertilizer comes under Ministry of Chemicals
- ❖ Fertilizers comes under Essential Commodities Act 1955
- ❖ Fertilizers is one of the 8 core industries (minimum share)

- उर्वरक विभाग रसायन मंत्रालय के अंतर्गत आता है
- उर्वरक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आता है
- उर्वरक 8 कोर सेक्टर में से एक है (न्यूनतम हिस्सेदारी)

GOBAR DHAN
GALVANIZING ORGANIC BIO-AGRO RESOURCES
A JAN ANDOLAN ON SAFE MANAGEMENT OF CATTLE AND ORGANIC WASTE

GOBAR-dhan: Waste to Wealth

- 2018, Ministry of Jal Shakti
- Under Swachh Bharat Mission (Grameen)
- Encourage conversion of organic waste to biogas and fertilizer

- 2018, जल शक्ति मंत्रालय
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत
- जैविक कचरे से बायोगैस और उर्वरक बनाने को प्रोत्साहित करना

PM Pranam Link

- ❑ Announced in budget 2023-24
- ❑ encourage States/UTs to promote alternative fertilizers and reduce use of chemical fertilizers.
- ❑ 50% of subsidy saved on chemical fertilizer (Urea, DAP, NPK, MOP) by a State/UT, compared to last 3 years, will be given to that State/UT as Grant.

- बजट 2023-24 में घोषित
- राज्यों/UT को वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना
- पिछले तीन वर्षों की तुलना में, रासायनिक उर्वरकों (यूरिया, DAP, NPK, MOP) पर किसी राज्य / UT द्वारा बचाई गई उर्वरक सब्सिडी का 50% हिस्सा उसे अनुदान के रूप में दिया जाएगा

Old name : Promotion of Alternate Nutrients for Agriculture Management
New name : Programme for Restoration, Awareness, Nourishment and Amelioration of Mother Earth

	2015	2023
Fertilizer subsidy	₹ 73,000 crore	₹ 2.5 lakh crore
Domestic urea production	225 LMT	284 LMT

→ 45 kg urea bag Actual cost ₹ 2200. MRP ₹ 242 (excluding neem coating charges & taxes)

World's largest fertilizer

- Consumer: #1 China #2 India
- Importer: #1 Brazil #2 India
- Producer: #1 China #2 USA #3 India

Entire subsidy is given by Central govt.
पूरी सब्सिडी केंद्र द्वारा दी जाती है ।

	Urea	Non-urea
Subsidy given to?	Company (Manufacturer/importer)	Company (Manufacturer/importer)
Subsidy based on?	Urea Subsidy scheme ▪ Difference between cost and selling price	Nutrient based subsidy scheme ▪ Amount of nutrients in fertilizer
Import?	Canalized ▪ Only 3 PSUs can import	Open General License ▪ Private companies are free to import

यूरिया	गैर-यूरिया
कंपनी (निर्माता/आयातक)	कंपनी (निर्माता/आयातक)
यूरिया सब्सिडी योजना ▪ लागत और विक्रय मूल्य के बीच अंतर	पोषक तत्व आधारित सब्सिडी योजना ▪ उर्वरक में पोषक तत्वों की मात्रा
कैनालाइज़्ड ▪ केवल 3 PSU आयात कर सकती हैं	ओपन जनरल लाइसेंस ▪ निजी कंपनियां आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं

Nutrients

- PRIMARY: Nitrogen, Phosphorous, Potassium
- SECONDARY: Calcium, Magnesium, Sulphur
- MICRO-NUTRIENTS: Iron, Copper, Manganese, Zinc, Boron, Chlorine, Molybdenum

30-06-2023 PIB

- ❑ Sulfur Coated Urea (Urea Gold)
- ❑ Cheaper and more efficient than neem coated urea

- सल्फर लेपित यूरिया (यूरिया गोल्ड)
- नीम लेपित यूरिया की तुलना में सस्ता और अधिक कुशल

Separate explanation videos are available in English & Hindi
अंग्रेजी और हिंदी में अलग-अलग वीडियो उपलब्ध हैं

21-Sep-2024 - The Hindu - India is running out of phosphorus. Does the solution lie in our sewage? Link

- 85% of global reserves of phosphorous are in Morocco.
- But here, it coexists with cadmium.
- Cadmium bioaccumulates in human body.
- Separating cadmium & phosphorous is expensive.

Domestic reserves:
- Jharkhand > Rajasthan > MP, etc
- But production is very less.
- India is world's largest importer of phosphorus.

Phosphorus as pollutant:
- It enters water bodies as agricultural run-off
- It creates harmful algal blooms

Solution:
- Recover phosphorus from urban sewage
- Use less chemical fertilizers

- फास्फोरस का 85% वैश्विक भंडार मोरक्को में हैं
- लेकिन यहां, फास्फोरस कैडमियम के साथ सह-अस्तित्व में है।
- कैडमियम मानव शरीर में जैवसंचय करता है।
- फॉस्फोरस और कैडमियम को अलग करना महंगा है।

घरेलू भंडार :
- झारखंड > राजस्थान > मध्य प्रदेश, आदि
- लेकिन उत्पादन बहुत कम है।
- भारत फास्फोरस का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक है।

प्रदूषक के रूप में फास्फोरस :
- यह कृषि अपवाह के रूप में जल निकायों में प्रवेश करता है
- यह हानिकारक अल्गल खिलता है

समाधान :
- शहरी सीवेज से फॉस्फोरस पुनर्प्राप्त करें
- रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग करें

Census on Minor Irrigation

Cultivable Command area	Classification
> 10,000 hectares	Major irrigation Project
2k – 10k hectares	Medium irrigation Project
< 2,000 hectares	Minor irrigation Project

Mostly uses surface water

Mostly uses groundwater

कृषि योग्य कमान क्षेत्र	वर्गीकरण
> 10,000 हेक्टेयर	प्रमुख सिंचाई परियोजना
2k – 10k हेक्टेयर	मध्यम सिंचाई परियोजना
< 2,000 हेक्टेयर	लघु सिंचाई परियोजना

ज्यादातर सतह के पानी का उपयोग करता है

ज्यादातर भूजल का उपयोग करता है

6th Census report on Minor Irrigation schemes

(1st census was done in 1986-87, report published in 1993)

- By Ministry of Jal Shakti during 2017-18
- Under centrally sponsored scheme "Irrigation Census".
- 2.3 crore MIS in 695 districts
- Increase of 14 lakh MIS compared to 5th census

- UP > Maharashtra > MP > Tamil Nadu
- Dug well > shallow tube well > medium tw > Deep tw

- 94.8% use groundwater. 5.2% use surface water
- 96.6% are privately owned. 3.4% have public ownership.
- In individually owned schemes, 18.1% are owned by women.
- 60% have single source of finance, of which 80% are financed by own savings of farmers.
- 97% are in use.

लघु सिंचाई योजनाओं पर छठी गणना रिपोर्ट

पहली गणना 1986-87 में हुई थी, रिपोर्ट 1993 में प्रकाशित हुई

- जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 2017-18 में क्या गया
- केंद्र प्रायोजित योजना "सिंचाई गणना" के तहत की गई
- 695 जिलों में 2.3 करोड़ MIS
- 5वीं जनगणना की तुलना में 14 लाख MIS की वृद्धि

- UP > महाराष्ट्र > MP > तमिलनाडु
- खोदे गए कुएँ > कम गहरे ट्यूबवेल > मध्यम tw > गहरे tw

- 94.8% भूजल आधारित हैं। 5.2% सतह जल आधारित हैं
- 96.6% निजी स्वामित्व में हैं। 3.4% सार्वजनिक स्वामित्व में हैं
- व्यक्तिगत स्वामित्व वाली योजनाओं में 18.1% का स्वामित्व महिलाओं के पास है।
- 60% योजनाओं में वित्त का एक ही स्रोत है, जिनमे से 80% किसान ने अपनी बचत से बनाई है
- 97% उपयोग में हैं

1st Census of water bodies

- It was done along with 6th census on Minor irrigation schemes
- It was done to create a national database of all water bodies
- It also used 2017-18 as reference year

- यह लघु सिंचाई योजनाओं की 6वीं गणना के साथ किया गया
- इससे सभी जल निकायों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाया गया
- इसने भी 2017-18 को संदर्भ वर्ष के रूप में इस्तेमाल किया

Rationalization of Minor Irrigation Statistics

- Launched in 1987-88 as Centrally sponsored scheme
- Later became part of Central sector scheme "Development of water resources information system (DWRIS)

- 1987-88 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया
- बाद में केंद्रीय क्षेत्र की योजना "जल संसाधन सूचना प्रणाली (DWRIS) का विकास" का हिस्सा बन गया

Prelims 2015 Consider the following statements :

1. Accelerated Irrigation Benefits programme was launched during 1996-97 to provide loan assistance to poor farmers.
2. Command Area Development Programme was launched in 1974-75 for the development of water-use efficiency.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) 1 only (b) 2 only
(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

1. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1996-97 में गरीब किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था।
2. कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल-उपयोग दक्षता के विकास के लिए शुरू किया गया था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

Seed

Three stages of seed production

1) Breeder seeds by ICAR
2) Foundation seeds by National Seeds Corp & pvt companies
3) Certified seeds by state governments

बीज उत्पादन के तीन चरण

प्रजनक बीज ICAR द्वारा
फाउंडेशन बीज राष्ट्रीय बीज निगम और निजी कंपनियों द्वारा
प्रमाणित बीज राज्य सरकारों द्वारा

Seeds Act 1966

- To regulate quality of certified seeds
- Seed certification is voluntary, but labelling is compulsory

बीज अधिनियम 1966

- प्रमाणित बीजों की गुणवत्ता को विनियमित करना
- बीज प्रमाणीकरण स्वैच्छिक है, लेकिन लेबल लगाना अनिवार्य है

PPVFR Act, 2001:

- Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act
- It protects intellectual property rights of plant breeders.
- Section 39 allows farmer to save, use, sow, resow, exchange, share or sell farm-saved seeds except the brand name.

- **PPVFR Act, 2001**: पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम
- यह पादप प्रजनकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करता है।
- धारा 39 किसान को ब्रांड नाम को छोड़कर खेत में बचाए गए बीजों को बचाने, उपयोग करने, बोने, दोबारा बोने, विनिमय करने, साझा करने या बेचने की अनुमति देता है।

Bharatiya Beej Sahakari Samiti Ltd

- formed in 2023 under Multi-State Cooperative Societies Act 2002
- It will produce, procure, distribute natural seeds under single brand

भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड

- बहु-राज्य सहकारी समिति ऐक्ट 2002 के तहत 2023 में गठित
- यह एकल ब्रांड के तहत प्राकृतिक बीजों का उत्पादन, खरीद और वितरण करेगी

SATHI portal

Seed Traceability, Authentication and Holistic Inventory

- Developed by NIC and MoA&FW
- Theme: Uttam Beej – Samriddh Kisan
- Seeds authenticity can be traced through QR code.
- Certified seeds can be sold only by licensed dealers to registered farmers.
- Farmers will get subsidy in bank through DBT (see page-11)

- NIC और कृषि मंत्रालय द्वारा विकसित
- थीम: उत्तम बीज - समृद्ध किसान
- QR कोड के जरिए बीजों की प्रामाणिकता का पता लगाया जा सकता है
- प्रमाणित बीज केवल लाइसेंस प्राप्त डीलरों द्वारा, पंजीकृत किसानों को बेचे जा सकते हैं
- किसानों को DBT के माध्यम से बैंक में सब्सिडी मिलेगी (pg-11)

Foodgrains

19-12-2023 PIB

- ❑ Existing schemes will be used to create various agri infra will be created at PACS level
- ❑ e.g. godowns, custom hiring center, processing units, Fair Price Shops, etc.

India's annual foodgrain production?

330 million tonne, usually increases slightly every year

- ❑ मौजूदा योजनाओं का उपयोग PACS स्तर पर विभिन्न कृषि बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए किया जाएगा
- ❑ जैसे गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयाँ, फेर प्राइस शॉप, आदि।

भारत का वार्षिक खाद्यान्न उत्पादन?

330 मिलियन टन, आमतौर पर हर साल थोड़ा बढ़ जाता है

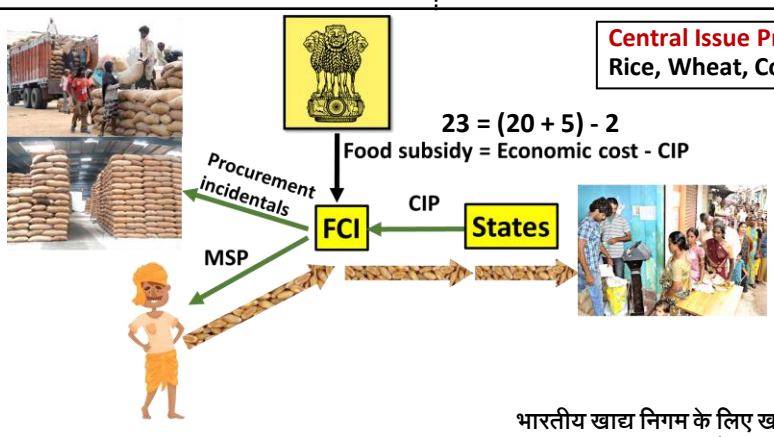

Prelims 2019: Economic cost of food grains to FCI is MSP and bonus (if any) paid to the farmers plus

(a) Transportation cost only (b) Interest cost only
(c) Procurement incidentals & distribution costs
(d) Procurement incidentals & charges for godowns

भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस (यदि कुछ है) के साथ साथ और क्या शामिल है ?

(a) केवल परिवहन लागत (b) केवल ब्याज लागत
(c) प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत
(d) प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा गोदामों के प्रभार

Inflation

	CPI Consumer Price Index	WPI Wholesale Price Index
Released by	Central Statistics Office, MoSPI	Office of Economic Adviser in DPIIT, MoCI
Base year	2011-12	2011-12
Frequency	monthly	monthly
Remarks	Goods & services. 46% weightage to food items. Used by MPC.	Goods only. 64% weightage Manufacturing

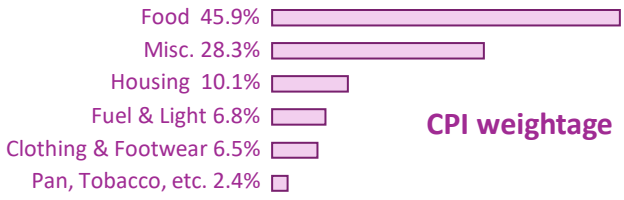

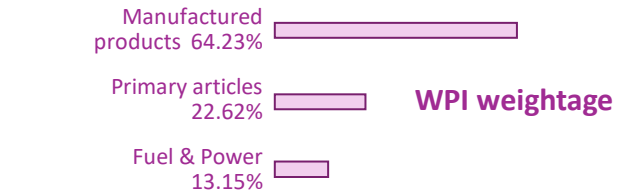

Price Monitoring

Market Intelligence and Early Warning System

- To monitor price of TOP Crops (Tomato, Onion, Potato)
- It generates alerts for intervention under Operation Greens

- TOP फसलों (टमाटर, प्याज, आलू) के मूल्य की निगरानी के लिए।
- यह ऑपरेशन ग्रीन्स के तहत हस्तक्षेप करने के लिए अलर्ट करता है

Price Monitoring Division

- It is monitors (retail & wholesale) price of (22) selected essential commodities, on daily basis
- It implements commodity-specific market intervention schemes to give temporary relief to consumers
- It comes under Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution

- यह दैनिक आधार पर चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं (22) के मूल्य (खुदरा और थोक) पर नज़र रखता है
- उपभोक्ताओं को अस्थायी राहत देने के लिए वस्तु-विशिष्ट बाजार हस्तक्षेप योजनाओं को लागू करता है
- यह उपभोक्ता मामलों के विभाग (उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय) के अंतर्गत आता है

Price Stabilization Fund

- Set up in 2014-15 under Deprt of Agriculture (MoA&FW)
- In 2016 it was transferred to Department of Consumer Affairs (MoCA,F,PD)
- To regulate price volatility of agri commodities like onion, potatoes and pulses
- Direct purchase is done from mandi to create strategic buffers
- Interest free loan is given to govt agencies for market intervention
- Funds are maintained by SFAC (Small Farmers Agribusiness Consortium), a society under Dept of Agri

- कृषि विभाग (MoA&FW) के अंतर्गत 2014-15 में स्थापित
- 2016 में इसे उपभोक्ता मामलों के विभाग (MoCA,F,PD) में स्थानांतरित कर दिया गया था
- प्याज, आलू और दालों जैसी कृषि उत्पादों की कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए
- स्ट्रेटेजिक बफर बनाने के लिए मंडी से सीधी खरीद की जाती है
- बाजार हस्तक्षेप के लिए सरकारी एजेंसियों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है
- इस फंड को SFAC (स्मॉल फार्मर्स एग्रीबिजनेस कंसोर्टियम) (कृषि विभाग की एक सोसायटी) द्वारा मेन्टेन किया जाता है

Comparison

MSP for 23 commodities

Pulses (gram, tur/arhar, moong, urad, masur)
Cereals rice, wheat, maize, sorghum, pearl millet, barley, ragi
Commercial crops - copra, sugarcane, cotton and raw jute
Oilseeds - rapeseed-mustard, groundnut, sunflower, soyabean, sesamum, safflower, nigerseed)

22 essential commodities for Price monitoring

Gram, Tur/Arhar, Moong, Urad, Masur
Rice, Wheat, Atta, Salt
Tea, Milk, Sugar, Gur
Mustard,Groundnut,Sunflower,Soya,Palm oil,Vanaspati
Tomato, Onion, Potato

Aquaculture

Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 was amended in 2023

तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 में वर्ष 2023 में संशोधित किया गया

Coastal Aquaculture Authority
- ❑ 2005, HQ Chennai
- ❑ It is a statutory body under Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying

Coastal Aquaculture
- ❑ It means cultivation of any aquatic life in coastal areas.
- ❑ It does not cover freshwater aquaculture.

One member from
- ❑ Each of the coastal states/UT
- ❑ Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying

Activities
- ❑ It prohibits aquaculture activities in ecologically sensitive areas.
- ❑ It allows some activities in CRZ:
  - ➢ Cage culture, seaweed culture, bi-value culture, marine ornamental fish culture, pearl oyster culture etc.
- ❑ It allows some activities in No Development Zone (NDZ) [200m from the HTL] :
  - ➢ Hatcheries
  - ➢ Nucleus Breeding Centres
  - ➢ Brood stock multiplication centres

Pollution
- ❑ It empowers CAA to set standards for emission or effluents discharge from aquaculture units.
- ❑ It upholds Polluter Pays Principle. Aquaculture unit owners must bear cost of environmental damage.

Penalties
- ❑ It replaces imprisonment with penalties.
- ❑ Centre will appoint Under-Secretary (or above) level officer to adjudicate penalties.

तटीय जलीय कृषि प्राधिकरण
- 2005, मुख्यालय चेन्नई
- यह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है

तटीय जलीय कृषि
- इसका अर्थ है तटीय क्षेत्रों में किसी भी जलीय जीवन की खेती।
- इसमे ताजे पानी की जलीय कृषि शामिल नहीं है।

एक सदस्य
- प्रत्येक तटीय राज्य / केंद्र शासित प्रदेश से
- मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय से

गतिविधियाँ
- यह पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में जलीय कृषि गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है।
- यह CRZ में कुछ गतिविधियों की अनुमति देता है:
  - ➢ केज कल्चर, समुद्री शैवाल कल्चर, द्वि-मूल्य कल्चर, समुद्री सजावटी मछली कल्चर, मोती सीप कल्चर आदि।
- यह नो डेवलपमेंट ज़ोन (NDZ) [HTL से 200m] में कुछ गतिविधियों की अनुमति देता है:
  - हैचरी
  - न्यूक्लियस प्रजनन केंद्र
  - ब्रूड स्टॉक गुणन केंद्र

प्रदूषण
- यह CAA को जलीय कृषि इकाइयों से उत्सर्जन या अपशिष्टों के निर्वहन के लिए मानक निर्धारित करने का अधिकार देता है।
- यह प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को कायम रखता है। एक्वाकल्चर इकाई के मालिकों को पर्यावरणीय क्षति की लागत वहन करनी होगी।

दंड
- यह कारावास को मौद्रिक दंड से बदलता है।
- केंद्र दंड पर निर्णय लेने के लिए अन्डर-सेक्रेटरी (या उससे ऊपर) स्तर के अधिकारी की नियुक्ति करेगा।

India's rank in fisheries:
#1 in inland capture fish production
#2 in aquaculture fish production
#3 in overall fish production
#4 in exports

मत्स्य पालन में भारत का स्थान:
अंतर्देशीय मछली उत्पादन में #1
जलीय कृषि मछली उत्पादन में #2
समग्र मछली उत्पादन में #3
निर्यात में #4

Livestock sector

Animal husbandry is in State list

पशुपालन राज्य सूची में है

Animal Husbandry Infra Development Fund
- Central sector scheme
- Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying
- To create processing infra for dairy, meat, animal feed
- For FPO, MSME, private companies. (~~marginal farmers~~)
- 90% loan; 3% interest subvention; 25% credit guarantee

- केंद्रीय क्षेत्र योजना
- मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
- डेयरी, मांस, पशु चारे के लिए प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के लिए
- FPO, MSME, निजी कंपनियों के लिए
- 90% ऋण; 3% ब्याज छूट; 25% क्रेडिट गारंटी

Livestock Census: (every 5 years)
- First time in 1919; 20th in 2019
- By Department of Animal Husbandry and Dairying.

पशुधन गणना: (प्रत्येक 5 वर्ष)
- 1919 में पहली बार; 2019 में 20वां
- पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा।

26-11-2023 PIB Animal Husbandry Statistics 2023 (increase/decrease is in last 5 years)

Milk production increase	UP > Rajasthan
Egg production increased	Andhra > Tamil Nadu
Meat production increased	UP > West Bengal
Wool production decreased	Rajasthan (48%) > J&K

Yellow	Edible oil
White	Milk
Pink	Meat
Green	Foodgrains
Grey	Coffee/Leather /Fertilizer
Blue	Fish
Silver	Egg

Turmeric

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1964083

India is the largest producer, consumer and exporter of turmeric in the world.

भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है।

Production

- ❑ 30 varieties, 20 states, 3.2 lakh hectare, 11.6 lakh tonnes (over 75% of global turmeric production).
- ❑ Maharashtra > Telangana > Karnataka > Tamil Nadu

उत्पादन

- 30 किस्में, 20 राज्य, 3.2 लाख हेक्टेयर, 11.6 लाख टन (वैश्विक हल्दी उत्पादन का 75%)
- महाराष्ट्र > तेलंगाना > कर्नाटक > तमिलनाडु

Export

- ❑ India has 62% share in world turmeric trade
- ❑ 1.5 lakh tonnes , worth $ 207 million exported
- ❑ Leading markets : Bangladesh, UAE, USA, Malaysia

निर्यात

- विश्व हल्दी व्यापार में भारत की 62% हिस्सेदारी है
- 1.5 लाख टन, 207 मिलियन डॉलर मूल्य का निर्यात
- प्रमुख बाजार: बांग्लादेश, UAE, USA, मलेशिया

Govt has established National Turmeric Board in Telangana

- under Ministry of Commerce
- Chairperson to be appointed by Central govt
- Secretary to be appointed by Department of Commerce

सरकार ने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की है

वाणिज्य मंत्रालय के तहत
अध्यक्ष को केंद्र सरकार नियुक्त करेगी
सचिव को वाणिज्य विभाग नियुक्त करेगा

It will have members from

- Three states
- Ministry of Agri
- Ministry of Ayush
- Department of Pharmaceuticals
- institutes involved in R&D
- representatives of farmers & exporters

इसमें सदस्य होंगे

- तीन राज्य से
- कृषि मंत्रालय से , आयुष मंत्रालय से
- फार्मास्यूटिकल्स विभाग से
- अनुसंधान एवं विकास के संस्थानों से
- किसानों और निर्यातकों के प्रतिनिधि

https://en.wikipedia.org/wiki/Turmeric

- It is native to Indian subcontinent and Southeast Asia
- It needs 20 and 30 °C temp and high annual rainfall.
- Curcumin is the main active ingredient in turmeric.

- यह भारतीय उपमहाद्वीप और दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है
- इसे 20-30° C तापमान और उच्च वर्षा चाहिए होती है
- करक्यूमिन हल्दी का मुख्य सक्रिय घटक है

https://www.indianspices.com/spice-catalog/turmeric-1.html

Botanical Name: Curcuma longa L.
Family: Zingiberaceae (ginger family)

DESCRIPTION

- Turmeric is the boiled, dried, rhizomes of Curcuma longa.
- It is a tropical crop cultivated up to 1200 meter mean sea level.
- It grows in light black, black clayey loams and red soils in irrigated and rainfed conditions.
- It cannot stand water logging or alkalinity.

USES

Food, medicines, biopesticide, cosmetics, etc.

वानस्पतिक नाम: करकुमा लोंगा L
परिवार: Zingiberaceae (अदरक परिवार)

विवरण

- हल्दी कुरकुमा लोंगा का उबला हुआ, सूखा, प्रकंद है।
- यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है जिसकी खेती समुद्र तल से 1200 मीटर तक की जाती है।
- यह सिंचित और वर्षा आधारित परिस्थितियों में हल्के काले, काली मिट्टी की दोमट और लाल मिट्टी में बढ़ता है।
- यह जल जमाव या क्षारीयता को बर्दाश्त नहीं कर पाता है।

उपयोग

भोजन, दवाएं, जैव कीटनाशक, सौंदर्य प्रसाधन, आदि।

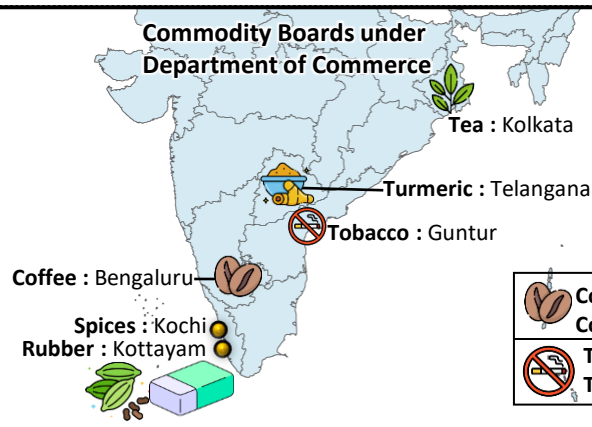

All of them are statutory bodies formed under some law.
Note: No law created for Turmeric Board as of April 2024

Coffee Board Coffee Act 1942	Rubber Board Rubber Act 1947	Tea Board Tea Act 1953
Tobacco Board Tobacco Board Act 1975	Spices Board Spices Board Act 1986	

Social Impact Bonds

- PPP for social impact projects.
- Type of Development Impact Bond

- 2020: Maharashtra's Pimpri Chinchwad Municipal Corporation and UNDP created India's first SIB.
- 2023: Nabard raised ₹1,040 crore via SIB. This is India's first externally certified AAA-rated SIB.
- 2023: NABARD announced 'Sustainability Bond Framework', which seeks to finance and refinance new or existing eligible green and social projects.

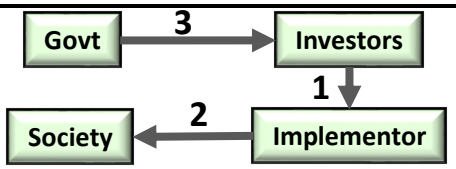

- 2020: महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम और UNDP ने भारत का पहला SIB बनाया
- 2023: नाबार्ड ने SIB के माध्यम से ₹1,040 करोड़ जुटाए। यह भारत का पहला बाहरी रूप से प्रमाणित AAA-रेटेड SIB है।
- 2023: NABARD ने 'सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड फ्रेमवर्क' की घोषणा की, जो नई या मौजूदा पात्र हरित और सामाजिक परियोजनाओं को वित्तपोषित और पुनर्वित्त करना चाहता है।

NABARD

- 1982; HQ: Mumbai; NABARD Act, 1981.
- On recommendation of B. Sivaramman Committee.
- Ownership: 100% Govt. of India.

- NABARD gives loans to banks/NBFC to give loan to farmers etc.
- NABARD does refinance, it does not directly give loan to people

Our initiatives are aimed at building an empowered and financially inclusive rural India through specific goal oriented departments which can be categorized broadly into three heads: Financial, Developmental and Supervision. Through these initiatives we touch almost every aspect of rural economy. From providing refinance support to building rural infrastructure; from preparing district level credit plans to guiding and motivating the banking industry in achieving these targets; from supervising Cooperative Banks and Regional Rural Banks (RRBs) to helping them develop sound banking practices and onboarding them to the CBS platform; from designing new development schemes to the implementation of GoI's development schemes; from training handicraft artisans to providing them a marketing platform for selling these articles.

Over the years our initiatives have touched millions of rural lives across the country. Our milestone achievements have been India's achievements as well. The SHG Bank Linkage Project launched by NABARD in 1992 has blossomed into the world's largest micro finance project. Kisan Credit Card, designed by us has become source of comfort for crores of farmers. We have financed one fifth of India's total rural infrastructure. We were pioneers in the field of watershed development as a tool for sustainable climate proofing. It's a long list indeed and we welcome you to understand us better.

ICAR

Indian Council of Agricultural Research

- 1929, HQ Delhi
- Under Ministry of Agri & Farmer Welfare
- Minister of Agriculture serves as its President

- ICAR is NOT a statutory body.
- It is a society under Societies Registration Act, 1860
- Earlier known as Imperial Council of Agricultural Research
- Formed on recommendation of Royal Commission on Agri

Some achievements:

- There are more than 113 ICAR institutes and 74 agriculture universities in India
- 1950-2021 : increased production of foodgrains 6.2 times, horticultural 11.5 times, fish 21.6 times, milk 13 times, eggs 70.7 times
- Rice varieties: Jaya, Padma, Ratna, Pusa Basmati, etc
- Wheat varieties: HD 2967, HD CSW 18, DBW 187, etc.
- Gene Bank: sent seeds to Svalbard (Norway), and helped establish National Gene Bank (Delhi)
- Biofortified crops: Solapur lal (pomegranate), etc.
- Stubble management: Pusa decomposer
- Biotech: Samrupa (world's first cloned buffalo), Pratham (world's first IVF buffalo calf)

Consultative Group for International Agricultural Research

- formed in 1971
- global partnership of organizations to reduce poverty, increase food security, etc.
- Not directly related to UN, FAO, ICAR, etc.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1929, मुख्यालय दिल्ली

- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत
- कृषि मंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं

- ICAR एक वैधानिक निकाय नहीं है।
- सोसायटी पंजीकरण ऐक्ट, 1860 के तहत एक सोसायटी है
- पुराना नाम- इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च
- कृषि पर रॉयल कमीशन की सिफारिश पर गठित

कुछ उपलब्धियां :

- 113 से अधिक icar संस्थान और 74 कृषि विश्वविद्यालय हैं
- 1950-2021 : खाद्यान्न उत्पादन में 6.2 गुना, बागवानी में 11.5 गुना, मछली में 21.6 गुना, दूध में 13 गुना, अंडे में 70.7 गुना
- चावल की किस्में: जया, पद्म, रत्न, पूसा बासमती, आदि
- गेहूं की किस्में: HD 2967, HD CSW 18, DBW 187, आदि।
- जीन बैंक: स्वालबार्ड (नॉर्वे) को बीज भेजे, और राष्ट्रीय जीन बैंक (दिल्ली) की स्थापना में मदद की
- बायोफोर्टिफाइड फसलें: सोलापुर लाल (अनार), आदि।
- पराली प्रबंधन: पूसा डीकंपोजर
- बायोटेक: स्वरूप (दुनिया का पहला क्लोन भैंस), प्रथम (दुनिया का पहला IVF भैंस बछड़ा)

अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान के लिए सलाहकार समूह

- 1971 में गठित
- गरीबी कम करने, खाद्य सुरक्षा बढ़ाने आदि के लिए संगठनों की वैश्विक भागीदारी।
- UN, FAO, ICAR, आदि से संबंधित नहीं है।